मंत्रालय का गठन करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के मंत्रालय का गठन करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ग) जी नहीं। पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए एक मंत्रालय के गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार एवं सामाजिक जागृति लाना

2808. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में "यूनिसेफ" की सहायता से शिक्षा के प्रसार और सामाजिक जागृति लाने हेतु चलाई जा रही/चलायी जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को शुरू करने के समय क्या लक्ष्य तय किया गया था;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई): (क) गुजरात से सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र स्थित भावनगर और आम्रेली जिलों में यूनिसेफ प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूली सुधार के उपायों तथा दाखिला देने और स्कूलों में बनाए रखने के अभियानों के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) से (घ) कार्यान्वयन हेतु दो जिलों में से प्रत्येक जिले के 1000 प्राथमिक स्कूलों को लिया गया है, दोनों जिलों में इन कार्यकलापों के लिए यूनिसेफ द्वारा 6 लाख रु० की राशि जारी की गई है।

Scheme formulated by Government for Upliftment of Minorities

2809. **SHRI K. RAHMAN KHAN:** Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the various Welfare Schemes, Government have formulated for the Socio-Economic and Educational Upliftment of the minorities in the country;

(b) the total assistance provided by Government under the various schemes State-wise;

(c) whether there are any other programmes for the minorities apart from the 15 Point Programme, if so, the details thereof; and

(d) the number of minorities benefited by such programmes State-wise?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) The 15-Point Programme for welfare of minorities announced in 1983 is being implemented at the Centre and State levels. The Programme envisages various welfare schemes for minorities for their socio-economic and educational upliftment.

The scheme of pre-examination coaching for weaker sections based on economic criteria is being implemented by the Ministry of Welfare as a Central scheme for the target groups consisting of OBCs and minorities with the objective of increasing their in-take in Government services and professional institutions.

The National Minorities Development & Finance Corporation is implementing schemes for promotion of self-employment ventures for the backward sections among minorities through various State Channelising Agencies. They are providing loans at concessional rates.

The Maulana Azad Education Foundation was set up for the purpose of promotion of educational activities among educationally backward sections of the

society particularly the minorities.

The Ministry of HRD Deptt. of Education has been implementing three separate schemes for the educational development of minorities in the minority concentration districts under the Programme of Action prepared in pursuance of National Policy on Education. The schemes are Area Intensive Programme, Modernisation of Madarsa Education and Community Polytechnics. The University Grants Commission is implementing a coaching scheme for minority candidates through the various Universities and Colleges. Under the UGC Coaching scheme candidates are provided free stipendary coaching.

(b) A statement giving details state-wise is annexed. *[Appendix* 175, *Annexure No.* 67].

(c) The 15-Point Programme contain all the schemes for welfare of minorities.

(d) Information is annexed *[Appendix* 175, *Annexure No.* 68].

केन्द्रीय विद्यालयों में शुल्क बढ़ाया जाना

2810. श्री सत्य प्रकाश मालवीय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988-89 और 1995 में केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिकी एवं उच्च स्तर की कक्षाओं में मासिक शिक्षा शुल्क कितना-कितना था और वर्ष 1988 से 1995 तक केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा शुल्क में कितनी बार वृद्धि की गई;

(ख) सरकार ने वर्ष 1988 और 1995 के बीच प्रतिमाह किस आधार पर शिक्षा शुल्क की दरों में वृद्धि की है;

(ग) क्या सरकार शिक्षा शुल्क को कम करके उसे वर्ष 1988 के स्तर तक ले आने के किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा की गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों में आठवीं कक्षा तक सभी छात्रों तथा बारहवीं कक्षा तक लड़कियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी और केन्द्रीय विद्यालय स्टाफ (कर्मचारियों) के बच्चों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। वर्ष 1988 से आज तक स्कूल के शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(ख) से (घ) वे प्रश्न नहीं उठते।

Report of "Due Diligence Process"

2811. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the answer to starred Question 267 given in the Rajya Sabha on 31st March, 1995 and state:

(a) whether the report of the "Due Diligence Process" for acquiring equity stakes in phosphatic fertilizer plant in USA/Russia has been submitted to Government;

(b) if so, the requirement of funds for acquiring the stakes; and

(c) if not, what is KRIBHCO's proposal for utilising the fund allocated for taking over these plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) The conclusions of the report of the 'Due Diligence Process' have been submitted to the Government.

(b) The report of the 'Due Diligence Process' was examined by a Committee of Senior Executive of KRIBHCO. As per the assessment of the Committee, the acquisition of equity stakes in a phosphatic fertilizer plant in USA/Russia was not found to be techno-economically viable.

(c) KRIBHCO had not specifically allocated funds for taking over these plants.